

अनुभव किया जाता है कि इन्हें कुछ समय पश्चात बन्द कर दिया जाय और इसी बीच रद्योग नई परिस्थितियों में अपने को ढाल लेगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय किया गया है कि सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता अब केवल कमी वाले क्षेत्र में ही स्थापित की जानी चाहिए। चूंक सीमेंट संतरण की स्थिति, फिलहाल अपेक्षाकृत अच्छी है और अगले कुछ वर्षों में भी ऐसी ही बनी रहने की आशा है, अतः इस उद्योग से कंट्रोल हटाने का यह अच्छा समय रहेगा। इन बातों को विचार में रखते हुए विद्यमान प्रबन्ध को समाप्त करने तथा 1 जनवरी, 1970 से सीमेंट के मूल्य और वितरण के सभी प्रकार के कंट्रोल हटा देने का निश्चय किया गया है। इस बीच उद्योग को कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट का उत्पादन करने का आयोजन करने का अवसर मिल जायेगा।

5. वर्तमान साधारण मूल्य तथा निर्माताओं को दिये जाने वाले कारखाने से चलते समय के मूल्य तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि के कारण उद्योग द्वारा समय-समय पर मूल्य में वृद्धि करना 1961 में प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है। 1 जनवरी, 1966 से सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ जाने से एस सधारण मूल्य बढ़ा देने के लिए उद्योग कुछ समय से जोर देता रहा है। उद्योग के इन दावों पर संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से विचार किया गया और यह महसूस किया गया कि कोयला के खान से चलते समय के मूल्य, रेल-भाड़े, बिजली शुल्क और वित्तीय मजरी बोर्ड पंचाट के कारण उनके वे दाव उचित ह। यद्यपि प्रशुल्क आयोग के लिए उत्पादन लागत में विद्यमान अत्यधिक असमानता को ध्यान में रखते हुए

1961 में इस उद्योग के लिए समान मूल्य की सिफारिश करना सम्भव नहीं था, तो भी सरकार का यह विचार था कि उद्योग के लिए समान मूल्य होने चाहिये जिससे उन एककों पर बचत करने पर जोर दिया जा सके जिनमें लागत अधिक आती हो और जिन एककों ने बचत की है उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। फिर भी सरकार को यह मानना पड़ा कि कुछ ऐसे एककों में जिनमें किन्हीं विशेष कारणवश अधिक लागत आती है उनके लिए कुछ समय के लिए अतिरिक्त मूल्य स्वीकार कर लिया जाये जिससे उनमें इस समय तक उत्पादन होता रहे जब तक कि वे समान्य मूल्य पर बचतपूर्ण ढंग से उत्पादन करने योग्य नहीं हो जाते। उद्योग के साथ समय-समय पर किए गए विचार विमर्श और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उद्योग स्वयं एक सामान्यतः समान मूल्य नीति रखने के पक्ष में है, आसाम सीमेंट्स (चेरापूंजी), जे० एण्ड के० मिनरल्स, (वुयान) और त्रावणकोर सीमेंट्स (कोट्टायम) को छोड़कर जो निम्न स्तर के एकक हैं और जिनके मामले में उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अलग से मूल्य निर्धारित करने पड़ेंगे, 16 अप्रैल, 1969 से कारखाने से चलते समय के 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन अधिकता मूल्य निश्चित करने का निर्णय किया गया है। यह 31 दिसम्बर, 1969 तक प्रभावी होगा जिस तारीख तक वर्तमान रेल भाड़ा सहित समानीकृत भाड़ा प्रबन्ध आदि लागू रहेंगे।

(ग) उपभोक्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

8 अश्व शक्ति ट्रेक्टरों का निर्माण

*764. श्री मोलहू प्रसाद : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवायकार्य मंत्री 13 मई, 1969 के तारा-

कित प्रश्न संख्या 1969 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना किसी विदेशी सहयोग के 8 अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये नई दिल्ली और मेरठ की जिन फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनके नाम और पते क्या हैं तथा ये प्रस्ताव किस किस तारीख को प्राप्त हुए थे ।

(ख) क्या बदनी स्थित परीक्षण केन्द्र में प्रोटो टाइप ट्रैक्टरों का परीक्षण किया गया है और क्या सरकार ने उसके बाद उक्त प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दो फर्मों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके नाम और पते ये हैं : भैसर्स सैलगयोकार इंजीनियर्स प्रा० लि०, डी०-9 साउथ एक्स-टेंसन, भाग-2 नई दिल्ली तथा मेसर्स डेल्टा इंजीनियरिंग क० प्रा० लि०, पोस्ट बाक्स नं० 35, मेरठ । विनियोजन, निर्माण कार्यक्रम आदि के औपचारिक विस्तृत विवरण सहित किसी भी पार्टी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । भारतीय जानकारी से ट्रैक्टर निर्माण करने की सूचना नई दिल्ली की फर्म से 17 अप्रैल, 1969 को तथा मेरठ की फर्म 28 मार्च 1969 को प्राप्त हुई थी ।

(ख) तथा (ग) : प्रोटो टाइप ट्रैक्टरी का परीक्षण अभी तक बुंचनी स्थित परीक्षण केन्द्र में नहीं किया गया है ।

Loss of Railway goods from Railway wagons

*765. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a very

large quantity of Railway goods is lost through wagon breaking, pilferage and theft every year;

(b) whether any estimate has been made by his Ministry about the extent of loss on this account in the different Railways;

(c) whether it is also a fact that the Railway employees are scared to take action against the criminals because adequate protection is not given to them and the local Police do not respond favourably in tracking down the criminals; and

(d) if so, what steps Government have taken to liaison with the State Governments to ensure that the Police help at the State level is spontaneous in tracking down criminals and the loss on this account is minimised?

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH): (a) Yes, Sir. The claims bill in the recent years has gone up, which is the only available index in determining the quantity of railway goods lost through wagon breaking, pilferage and theft.

(b) Yes, Sir. A statement regarding the loss (claims—compensation) on this account on the various zonal railways is placed on the table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1830[69].

(c) No, Sir. Railway Protection Force staff who are responsible to provide better protection and security to the railway property, have been taking suitable action against the criminals found committing thefts. They have also been engaged in several encounters with gangs of armed criminals and have been successful in safeguarding the railway property from being looted. Local Police have also been responding favourably in tracking down the criminals.

(d) Close liaison at all levels is maintained with the State Police for